an>

Title: Need to provide basic facilities to the people living in unauthorized colonies in Delhi.

श्री रमेश विधूड़ी (दक्षिण दिल्ली)ः मैं सरकार का ध्यान दिल्ली में अनधिकृत कालोनी में रह रहे 35 लाख लोगों की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूँ। दिल्ली में 1639 अनधिकृत कालोनी हैं जिसमें करीब 35 लाख लोग रहते हैं। इनकी समस्याओं पर पिछली सभी सरकारों ने ध्यान दिया पर 2014 में केन्द्र में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी तो एनडीए ने अनधिकृत कालोनी की समस्या को संज्ञान में लेते हुए मातृ महीने में 29 दिसम्बर, 2014 को 895 कालोनियों को अपूव कर दिया ताकि इन कालोनियों में विकास कराया जा सके और केन्द्र सरकार द्वारा आदेश दिए गए कि दिल्ली सरकार इन कालोनियों को अपूवड मानकर इन कालोनियों में demarcation आदि के काम शुरू कराए और जो कालोनी ASI, सरकारी जमीन आदि पर है उन कालोनियों को demarcate किया जाए पर डेढ़ साल से दिल्ली सरकार अनधिकृत कालोनियों के विकास के काम पर आँख मूंद कर बैठी हुई है और कोई भी काम इस दिशा में दिल्ली सरकार ने नहीं किया है।

हाल में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने भी माननीय उप राज्यपाल को दिल्ली का प्रशासनिक हेड बताया है इसलिए आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि इस मामले में तेजी लाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय दिल्ली सरकार को निर्देश दें। इस मानसून में यहां रहने वाले लोगों के घर तालाब बन गए, सड़कों पर पानी जमा हो गया जिस वजह से इन अनधिकृत कालोनी जैसे प्रह्लादपुर, मोडबंद, संगम विहार, रंगपुरी, आयानगर आदि में रहने वाले 35 लाख लोगों को इन कालोनियों में नागरिक सुविधाओं के अभाव में भीषण संकट का सामना करना पड़ रहा है।

मेरा अनुरोध है कि शहरी विकास मंत्रालय दिल्ली सरकार से इस काम को जल्द से जल्द कराए ताकि इन कालोनियों में रहने वाले लोगों को इन समस्याओं से निजात मिल सके और इन कालोनियों में जल्द विकास कार्य शुरू कराए जा सके।